



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-1250  
km. 30  
Depth- 1000  
CFB. 220

सं. 117]

No. 117]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2004/फाल्गुन 15, 1925  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2004/PHALGUNA 15, 1925

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2004

प्रभारी  
पा० वि० एकक

सा.का.नि. 175(अ).— केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68)

की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2004 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (1) में खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(चक) रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नई दिल्ली ;”.

3. उक्त नियमों के नियम 4 में, उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(6) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उसके कार्यकारी ग्रुप की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों द्वारा आने और जाने के लिए की गई यात्रा के संबंध में, वे सदस्य रेलगाड़ियों द्वारा ( जिसके अंतर्गत राजधानी एक्सप्रेस है ) रेल सुविधा की प्रथम श्रेणी या टू टायर वातानुकूलित

श्रेणी और यात्रा की वास्तविक रीति के ऐसे भार या लागत के दावे इनमें से जो भी कम हो हकदार होंगे । गैर सरकारी सदस्य, द्वीपसमूह राज्यक्षेत्र से घरेलू वायुयान सेवा में हवाई यात्रा (मितव्ययी श्रेणी) में निकटतम मुख्य भू-वायुपत्तन तक आने और जाने तथा उसके पश्चात् रेल भाड़े के हकदार होंगे । ऐसे गैर सरकारी सदस्य जो ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनकी यात्रा के लिए ज्येष्ठ नागरिक रियायत वायुभाड़े का उपभोग करने पर घरेलू वायु सेवा में वायुयान यात्रा ( मितव्ययी श्रेणी ) में आने और जाने के हकदार होंगे । परंतु यह तब जब कि यात्रा की दूरी एक हजार किलोमीटर या उससे अधिक है । गैर सरकारी सदस्य, उनके दैनिक भत्ते, आवास भत्ते, स्थानीय वाहन भत्ते, जो उनके निवास स्थान से स्टेशन/वायुयान पत्तन तक और वहां से बैठक के स्थान तक और उसके पश्चात् वापस लौटने के लिए व्यय की क्षतिपूर्ति करने के लिए, एक हजार रूपए प्रति दिन की राशि के आनुषंगिक प्रभार के रूप में हकदार होंगे । इस उपनियम के अधीन किया गया प्रत्येक दावा यह प्रमाणित करने के अध्वधीन होगा कि सदस्य किसी अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग या संगठन से केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद या उसके किसी कार्यकारी ग्रुप की बैठक में भाग लेने के लिए उसके दौरे के दौरान किसी प्रसुविधा का दावा नहीं करेगा । बैठक के स्थान पर निवेश घरेलू स्थान गैर सरकारी सदस्यों को, शहर के उनके अपने वर्गीकरण के अवसर पर दो सौ रूपए प्रतिदिन तक के दैनिक भत्ते की क्षतिपूर्ति करने के लिए समेकित वाहन या प्रभार या अनुषंगिक प्रभार संदत्त किया जाएगा । परिषद या उसके कार्यकारी ग्रुप की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद सदस्य ऐसी दर पर , जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय हो यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ” ।

4. उक्त नियमों के नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 9क. जिला फोरम के समक्ष परिवाद फाइल करने के लिए फीस -

(1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी जिला फोरम को फाइल किए गए प्रत्येक परिवाद के साथ नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में लिखित क्रॉस मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में या राज्य आयोग के रजिस्ट्रार के पक्ष में लिखित किसी क्रॉस भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से फीस होगी और जो उस स्थान पर संदेय होगी जहां राज्य आयोग अवस्थित है ।

संबंधित जिला फोरम इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक फीस की राशि को राज्य सरकार प्राप्ति लेखा में जमा करेगा ।

सारणी

क्रम सं.	माल या सेवा का मूल्य और दावाकृत प्रतिकर	संदेय फीस की राशि
(1)	(2)	(3)
	जिला फोरम	
(1)	एक लाख रुपए तक	100रु.
(2)	एक लाख रुपए और उससे ऊपर किन्तु पांच लाख रुपए से कम	200रु.
(3)	पांच लाख रुपए और उससे ऊपर किन्तु दस लाख रुपए से कम	400रु.
(4)	दस लाख रुपए और उससे ऊपर किन्तु बीस लाख रुपए से अनधिक	500रु.

5. उक्त नियम के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“ 10क. उपभोक्ता कल्याण निधि में जुमाने का तब जमा किया जाना उपभोक्ताओं की सुविधाजनक रूप में पहचान नहीं की जा सकती है ।

(1) जहां, राष्ट्रीय आयोग द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (जख) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे विरोधी पक्षकार को ऐसी राशि का संदाय करने का

- (2) निदेश देते हुए, जिसके कारण अनेक उपभोक्ताओं को सेवा के विरुद्ध परिवाद या अभिकथित कमी के माल के कारण हुई किसी हानि या क्षति की बाबत उसके द्वारा अवधारित की गई है जिनकी सुविधाजनक रूप में पहचान नहीं की जा सकती है, कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां राष्ट्रीय आयोग द्वारा ऐसी राशि, केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 12(ग) के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा की जाएगी । ”
- (3) उक्त निधि में जमा किसी राशि का उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 1992 के उपबन्धों के अनुसार उपयोग किया जाएगा ।

**10ख राष्ट्रीय आयोग में सदस्यों की संख्या :-** राष्ट्रीय आयोग चार सदस्यों से अन्धून और छह सदस्यों से अनधिक से मिलकर बनेगा और जिनमें कम से कम एक महिला होगी । ” ।

#### 6. उक्त नियमों के नियम 12 में, -

(क) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपनियम (3) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (क) अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा और केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित करते हुए किसी समय अपना पदत्याग सकेगा किन्तु ऐसा पद केवल तब रिक्त होगा जब केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है ;” ;

(ग) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (6) जब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या ऐसे पद का धारण करने वाला कोई व्यक्ति अनुपस्थिति या अन्यथा के कारण अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब उसका उसे धारा 22घ के परन्तुक में उपबन्धित अन्यथा के सिवाय, राष्ट्रीय आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा निर्वहन किया जाएगा । ” ।

7. उक्त नियमों के नियम 13 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य उस उपनियम के खण्ड (घ), खण्ड (ङ) और खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट आधारों पर और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के किसी पीठासीन न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, जिसमें राष्ट्रीय आयोग के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई हो और उन आरोपों की बाबत उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो, तथा उसे दोषी पाया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय पद से नहीं हटाया जाएगा।”

8. उक्त नियमों के नियम (14) में, -

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ (1क) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक परिवाद के साथ नियम 9क में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत फीस लगी होगी। ” ;

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) राष्ट्रीय आयोग, उसके समक्ष किसी परिवाद के निपटान में, यथासाध्य प्रक्रिया और शर्तों का, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा प्राप्त परिवादों के संबंध में धारा 12 और धारा 13 में यथा अधिकथित आस्थगन को शासित करने वाले उपबंध भी हैं, ऐसे उपान्तरण सहित जो आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाएं, पालन करेगा। ” ;

(ग) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् निपटान किए जा रहे किसी परिवाद की दशा में, राष्ट्रीय आयोग ऐसे निपटान में विलम्ब के कारणों को अभिलिखित करेगा।”

9. उक्त नियमों के नियम (14) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“14क. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपीलें - धारा 19 के अनुसार फाइल की गई प्रत्येक अपील के साथ उक्त धारा के दूसरे परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट राशि लगी होगी और ऐसे राशि रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में, दिल्ली में संदेय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में लिखित एक क्रास मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित की जा सकेगी। राष्ट्रीय आयोग, उसके समक्ष फाइल की गई अपीलों का निपटान करते समय धारा 19 और धारा 19क के उपबन्धों का, जो आयोग के समक्ष फाइल की गई अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपेक्षित हों, पालन करेगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम में, “राष्ट्रीयकृत बैंक” से, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्समान नया बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्समय नया बैंक अभिप्रेत है।

10. उक्त नियमों के नियम 15 में,-

(क) उपनियम (3) में, “के अभिप्रमाणित प्रतिलिपि” शब्दों के स्थान पर “नियम 14क में यथानिर्दिष्ट क्रास मांगदेय ड्राफ्ट और एक अधिप्रमाणित प्रति” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(8) राष्ट्रीय आयोग द्वारा साधारण तौर पर कोई स्थगन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि पर्याप्त हेतुक दर्शित न किया गया हो और स्थगन मंजूर करने के कारणों को आयोग द्वारा अभिलिखित न किया गया हो। राष्ट्रीय आयोग ऐसे निबन्धनों पर जो वह उपयुक्त समझे और कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर जिसके

कारणों को अभिलिखित किया जा सकेगा, स्वप्रेरणा से अपील की सुनवाई को भी स्थगित कर सकेगा । अपील का इसके स्वीकार करने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर यथासंभव शीघ्र विनिश्चय किया जाएगा । इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् निपटान की जा रही किसी अपील की दशा में राष्ट्रीय आयोग उक्त अपील के निपटान के समय उसके कारणों को अभिलिखित करेगा । ”

11. उक्त नियमों के नियम 15क के उपनियम (1) में, “ कम से कम दो सदस्यों द्वारा किया जाएगा ” शब्दों के स्थान पर “ कम से कम दो सदस्यों द्वारा तब के सिवाय जब कोई पीठ राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और एक या अधिक सदस्यों से, जो उपयुक्त समझा जाए, मिलकर गठित की जाती है, किया जाएगा ”, शब्द जोड़े जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के नियम 15क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 16. उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलों में राशि का निक्षेप करने की रीति - धारा 23 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई प्रत्येक अपील के साथ उस धारा के दूसरे परन्तुक में यथाउपबंधित कोई राशि होगी और ऐसी राशि रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय के पक्ष में, दिल्ली में संदेय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में लिखित किसी क्रास मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण - इस नियम में, “ राष्ट्रीयकृत बैंक ” से, बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 5 ) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्समान नया बैंक या बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण ) अधिनियम, 1980 ( 1980 का 40 ) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्समय नया बैंक अभिप्रेत है ।

[ फा. सं. 10(2)/2003-सीपीयू ]

सतवंत रेड्डी, अपर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि.सं0 398 (अ) तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

1. साकानि 533 (अ) तारीख 14.8.1991

2. साकानि 800 (अ) तारीख 30.12.1993
3. साकानि 522(अ) तारीख 20.6.1994
4. साकानि 605 (अ) तारीख 30.8.1995
5. साकानि 759 (अ) तारीख 21.11.1995 और
6. साकानि 95 (अ) तारीख 27.2.1997

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department of Consumer Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th March, 2004

**G.S.R. 175(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely:-

**1. Short title, extent and commencement.** - (1) these rules may be called the Consumer Protection (Amendment) Rules, 2004.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the Consumer Protection Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (1), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-**

"(fa) The Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi,".

**3. In rule 4 of the said rules, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-**

" (6) In connection with the journey undertaken to and fro by the non-official members for attending the meeting of the Central Consumer Protection Council or its working group, they shall be entitled to avail first class or two-tier air-



conditioned class of railway accommodation by all trains (including Rajdhani Express) and claim such fare or cost of actual mode of travel, whichever is less. The non-official members from Island territories shall be entitled to, to and fro air journey (economy class) in domestic airlines from the Islands to the nearest main-land airport and thereafter rail fare by entitled class. The non-official members who are senior citizens shall be entitled to, to and fro air-journey (economy class) in domestic airlines on availing senior citizen concessional air fare for their journeys provided the distance being travelled is 1000 kms or above. The non-official members shall be entitled to a sum of Rs.1000 per day as incidental charges to cover the expenditure towards their daily allowance, lodging, local conveyance from residence to the station/airport and from station/airport to the venue of meeting and vice-versa. Every claim made under this sub-rule shall be subject to certifying that the member will not claim any benefit from any other Central Government Ministry, Department or Organization during his visit for attending the meeting of the Central Consumer Protection Council or any of its Working Group. Local non-official members residing at the place of the venue of the meeting, shall be paid consolidated conveyance, hire charges and incidental charges to cover the daily allowances, to the tune of Rs. 200 per diem irrespective of the classification of the city. Members of Parliament attending meetings of the Council or its Working Group shall be entitled to travelling and daily allowances at such rates as are admissible to such members".

**4. After rule 9 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-**

**"9A. Fee for making complaints before District Forum -** (1) Every complaint filed under sub-section (1) of section 12 with a District Forum shall be accompanied by a fee, as specified in the table given below in the form of crossed Demand Draft drawn on a nationalised bank or through a crossed Indian Postal Order drawn in favour of the Registrar of the State Commission and payable at the respective place where the State Commission is situated. The

73661/04-2

concerned District Forum shall deposit the amount of fee so received in the State Government Receipt Account.

**TABLE**

Sl. No.	Value of goods or services and the compensation claimed	Amount of fee payable
(1)	(2)	(3)
	<b>District Forum</b>	
(1)	Upto one lakh rupees	Rs.100
(2)	One lakh rupees and above but less than five lakh rupees	Rs.200
(3)	Five lakh rupees and above but less than Rs.10 lakh	Rs.400
(4)	Ten lakh rupees and above but not exceeding twenty lakh rupees	Rs.500

5. After rule 10 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely.-

**"10A. Credit of the fine into the Consumer Welfare Fund when consumers are not identified conveniently.**

(1) Where an order is passed by the National Commission in exercise of the powers vested under clause (hb) of sub-section (1) of section 14 directing the opposite party to pay such amount as determined by it on account of loss or injury suffered due to defects in goods complained against or alleged deficiency of service to a large number of consumers, who are not identifiable conveniently,

such sum shall be credited by the National Commission in the Consumer Welfare Fund established by the Central Government under section 12 (C) of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

(2) Any amount credited to the said Fund shall be utilized in accordance with the provisions of the Consumer Welfare Fund Rules, 1992.

**10 B Number of Members in the National Commission:** - The National Commission shall consist of not less than four members and not more than six members and at least one of them shall be a woman".

**6. In rule 12 of the said rules, -**

(a) Sub-rule (2) shall be omitted;

(b) in sub-rule (3), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) by writing under his hand and addressed to the Central Government resign his office at any time but his office shall become vacant only when such resignation is accepted by the Central Government";

(c) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) when the office of the President of the National Commission is vacant or a person occupying such office is by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the same shall, save as otherwise provided in the proviso to section 22D be performed by the senior most member of the National Commission".

**7. In rule 13 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -**

"(2) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), the President or any member of the National Commission shall not be removed from his office

except by an order made by the Central Government on the grounds specified in clauses (d), (e) and (f) of that sub-rule and after an inquiry held by a sitting Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India in which the President or member of the National Commission, as the case may be, has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges and found guilty."

**8. In rule 14 of the said rules,-**

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) Every complaint under sub-rule (1) shall be accompanied by the relevant fee as is specified in rule 9A.";

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The National Commission shall, in disposal of any complaint before it, as far as possible, follow the procedure and conditions including the provisions governing adjournments as laid down in sections 12 and 13 in relation to the complaints received by the District Forum, with such modification as may be considered necessary by the Commission.";

(c) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) In the event of a complaint being disposed of after the period specified in sub-rule (4), the National Commission shall record in writing, the reasons for the delay in such disposal."

**9. After rule 14 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-**

**" 14A. Appeals before National Commission .-** Every appeal filed in terms of section 19 shall be accompanied by such amount as specified in the second proviso to the said section and such amount may be remitted in the form

of a crossed Demand Draft drawn on a nationalized bank in favour of the Registrar, National Commission, payable at Delhi. The National Commission dealing with the appeals filed before them shall follow the provisions of section 19 and 19A as may be required to hear the appeals filed before the Commission.

*Explanation.-* In this rule, "nationalized bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).

**10. In rule 15 of the said rules, –**

**(a) in sub-rule (3), for the words "accompanied by a certified copy", the words " accompanied by a crossed demand draft as referred to in rule 14A and by a certified copy" shall be substituted.**

**(b) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-**

" (8) No adjournment shall ordinarily be granted by the National Commission, unless sufficient cause is shown and the reasons for grant of adjournment have been recorded in writing by the Commission. The National Commission may also adjourn the hearing of the appeal suo motu, on such terms as it may think fit and at any stage of the proceedings for reasons to be recorded in writing. The appeal shall be decided, as far as possible, within ninety days from the date of its admission. In the event of an appeal being disposed of after the period so specified, the National Commission shall record in writing the reasons of the same at the time of disposal of the said appeal.

**11. In rule 15A of the said rules, in sub-rule (1), after the words "sitting together", occurring at the end, the words" except when a bench is constituted by the President of the National Commission with one or more members as he may deem fit" shall be added.**

**12. After rule 15A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely.-**

**" 16. Manner of deposit of amount in appeals before Supreme Court -**  
Every appeal filed before the Supreme Court in terms of section 23 shall be accompanied by an amount as provided in the second proviso to that section and such amount may be remitted in the form of a crossed Demand Draft drawn on a nationalized bank in favour of Registrar, Supreme Court, payable at Delhi.

*Explanation.-* In this rule, "nationalized bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980)".

[F. No. 10(2)/2003-CPU]

SATWANT REDDY, Addl. Secy.

**Note :-** The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 398(E) dated 15th April, 1987 and subsequently amended vide;

1. GSR 533(E) dated 14.8.1991.
2. GSR 800(E) dated 30.12.1993
3. GSR 522(E) dated 22.6.1994
4. GSR 605(E) dated 30.8.1995
5. GSR 759(E) dated 21.11.1995, and
6. GSR 95(E) dated 27.2.1997.